

## राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण

### प्रलिस के लिये:

समानता का अधिकार, महिला आरक्षण वधियक, महिला सशक्तीकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान ।

### मेन्स के लिये:

राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास, मानव संसाधन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक राजनीतिक दल ने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण वधियक को [संसद](#) में पेश करने का आह्वान किया ।

- [राज्यसभा](#) ने 9 मार्च, 2010 को [महिला आरक्षण वधियक](#) पारित किया था । हालाँकि लोकसभा ने कभी भी वधियक पर मतदान नहीं किया । इस वधियक को समाप्त कर दिया गया क्योंकि यह अभी तक [लोकसभा](#) में लंबित था ।

## भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण की पृष्ठभूमि:

- राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामने आया । वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तीन महिला नकारियों, नेताओं- बेगम शाह नवाज़ और [सरोजिनी नायडू](#) द्वारा नए संवैधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी **आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत** किया गए थे ।
- महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिरेक्षण योजना में वर्ष 1988 में सफ़िरशि की गई थी कि महिलाओं को [पंचायत](#) स्तर से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ।
  - इन सफ़िरशियों ने संवैधान के [73वें और 74वें संशोधन](#) के ऐतिहासिक अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया, जो सभी राज्य सरकारों को क्रमशः पंचायती राज संस्थानों एवं इसके हर स्तर पर अध्यक्ष पदों तथा शहरी स्थानीय नकारियों में महिलाओं हेतु एक-तह्राई सीटें आरक्षण करने का आदेश देती हैं । इन सीटों में एक-तह्राई सीटें [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति](#) की महिलाओं के लिये आरक्षित हैं ।
  - महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों ने स्थानीय नकारियों में महिलाओं के लिये 50% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधान किये हैं ।

## महिला प्रतिनिधित्व वधियक:

- वधियक के बारे में:
  - महिला आरक्षण वधियक में महिलाओं के लिये [लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित](#) करने का प्रस्ताव है ।
  - आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से आवंटित किया जा सकता है ।
  - इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा ।
- आवश्यकता:
  - [ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022](#) के अनुसार, भारत राजनीतिक अधिकारिता (संसद में महिलाओं का प्रतिशत और मंत्री पद) आयाम में 146 में से 48वें स्थान पर है ।
    - इस रैंक के बावजूद भारत का स्कोर 0.267 है जो काफी कम है । इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंक वाले कुछ देशों का स्कोर कहीं बेहतर है । उदाहरण के लिये [आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है ।](#)
  - महिलाओं का आत्म-प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय का अधिकार ।
  - विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, [महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों ने गाँवों में समाज के विकास और समग्र भलाई के लिये सहायनीय काम किया है तथा उनमें से कई नसिंदेह बड़े पैमाने पर काम करना चाहेंगी](#); हालाँकि वे भारत की राजनीतिक संरचना में विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं ।

### ■ बलि के खिलाफ तरक:

- महिलाएँ कोई सजातीय समुदाय नहीं हैं, जैसे कौकोई जातिसमूह। इसलिये महिलाओं के लिये जाति-आधारित आरक्षण हेतु जो तरक दिये गए हैं, वे उचित नहीं हैं।
- महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का कुछ लोगों द्वारा वरिध कया जाता है। वे दावा करते हैं कि ऐसा करने से संवधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। यदि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो उनका तरक है कि महिलाएँ योग्यता के आधार पर प्रतस्पर्धा नहीं करेंगी, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गरिबत आ सकती है।

## भारतीय राजनीत में महिलाओं का प्रतनिधित्व:

### ■ स्वतंत्रता से पहले:

- पतिसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों और मानसकता ने ऐतहासिक रूप से भारत में महिलाओं को हाशिये पर रखने और उनका शोषण करने की अनुमति दी है।
- सामाजिक सुधारों की शुरुआत और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी: महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली योगदान दिया, जो बंगाल में **स्वदेशी आंदोलन (1905-08)** के साथ शुरु हुआ, जिसमें महिलाओं ने राजनीतिक प्रदर्शनों का आयोजन, संसाधन जुटाना एवं आंदोलनों में नेतृत्व की स्थिति संभाली।

### ■ आज़ादी के बाद:

- भारत के संवधान ने नरिधारित कया है कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रपुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार करेंगे।
- वर्तमान में भारतीय संसद की लगभग 14.4% सदस्य महिलाएँ हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हालाँकि अंतर-संसदीय संघ के अनुसार, भारत के नमिन सदन में नेपाल, पाकस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की तुलना में महिलाओं का प्रतशित कम है।
- **भारत नरिवाचन आयोग (Election Commission of India- ECI)** के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2021 में महिला प्रतनिधि संसद के कुल सदस्यों का 10.5% हैं।
- भारत में सभी राज्य वधानसभाओं में महिला सदस्यों (MLA) के लिये परदृश्य और भी बढतर है, जिसका राष्ट्रीय औसत 9% है। आज़ादी के पछिले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतनिधित्व 10% भी नहीं बढा है।

## भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मूल्यांकन हेतु मानदंड:

### ■ मतदाता के रूप में महिलाएँ:

- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में लगभग उतनी ही महिलाओं ने मतदान कया, यह राजनीति में लैंगिक समानता की दशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे "कवाइट रिवोल्यूशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट" कहा गया गया है। इस बढती भागीदारी के वशिषकर वर्ष 1990 के दशक के दौरान से कई कारण रहे हैं।

### ■ उम्मीदवार के रूप में महिलाएँ:

- सामान्यतः संसदीय चुनावों में महिला उम्मीदवारों का अनुपात समय के साथ बढा है लेकिन पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में यह कम रहा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,049 उम्मीदवारों में 9% से कम महिलाएँ थीं।

## भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतनिधित्व को बेहतर करने हेतु उपाय:

- भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतनिधित्व अनेक वर्षों से चर्चा का वषिय रहा है और इसमें कुछ प्रगति भी हुई है कति अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना शेष है। भारतीय राजनीति में महिलाओं के बेहतर प्रतनिधित्व हेतु कुछ तरीके इस प्रकार हैं:
  - सीटों का आरक्षण: स्थानीय नकियों और वधानसभाओं में महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण राजनीति में महिलाओं के प्रतनिधित्व में वृद्धा करने का एक सफल तरीका रहा है। महिलाओं को नरिणय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु ऐसी और अधिक आरक्षण नीतियाँ लागू की जा सकती हैं।
  - जागरूक और शकषति करना: महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में भागीदारी के महत्व के वषिय में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। शैक्षिक कार्यक्रम तथा जागरूकता अभियान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढाने में मदद कर सकते हैं।
  - लगी आधारत हसि और उत्पीडन को रोकने हेतु आवश्यक कदम: लगी आधारत हसि एवं उत्पीडन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की दशा में प्रमुख बाधाएँ हैं। नीति तथा वधिक उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने से राजनीति में महिलाओं के लिये सुरक्षित और अधिक सहायक वातावरण तैयार हो सकता है।
  - चुनावी प्रक्रिया में सुधार: अधिक महिलाओं का चयन सुनश्चित करने हेतु आनुपातिक प्रतनिधित्व और अधमिन्य मतदान प्रणाली को लागू करने जैसे सुधार राजनीति में महिलाओं के प्रतनिधित्व को बढावा दे सकते हैं।
- भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढाने के उपाय सीमति हैं। दीर्घकालिक प्रभाव के लिये कई चुनौतियों से नपिटने हेतु एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. "स्थानीय स्वशासन के संस्थानों में महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का भारतीय राजनीतिक प्रक्रम के पतिसत्तात्मक अभलक्षण पर एक सीमति प्रभाव पडा है।" टपिणी कीजयि। (2019)

[स्रोत: द हिंदू](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reservation-for-women-in-politics>

